ई–बिज़ मिशन मोड परियोजना में आई तेजी

राज्य सरकार के विभागों के नोडल अधिकारियों की दो–दिवसीय कार्यषाला

लखनऊ, 07 मई, 2015

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन हेतु सम्बन्धित विभागों की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए कई नवीन कदम उठा रही राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ई–बिज़ मिशन मोड पोर्टल से राज्य सरकार के विभागों की सेवाओं को जोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

इस सम्बन्ध में आज यहाँ दो–दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई, जिसमें राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों के नोडल अधिकारियों को इस प्रणाली के उद्देश्यों और कार्यविधि से परिचित कराया जा रहा है।

आज भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग के अधिकारी तथा इन्फोसिस के कर्मियों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ इस कार्यशाला का संचालन किया। प्रदूषण नियंत्रण, पावर, खाद्य, औषधि, स्थानीय निकाय, स्टाम्प व निबन्धन, श्रम आदि विभाग इसमें सम्मिलित थे।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निवेशकों व उद्यमियों को एकल विण्डो क्लीयरेन्स प्रणाली उपलब्ध कराना है।

विशेष सचिव एवं उद्योग बन्धु की संयुक्त अधिशासी निदेशक, सुश्री कंचन वर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला के दौरान भारत सरकार की टीम इस परियोजना में जोड़ने हेतु राज्य के विभिन्न विभागों की तैयारी की वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करेगी तथा इसी आधार पर ई–बिज़ मिशन मोड प्रोजेक्ट के विभिन्न स्तरों से जोड़ने का कार्य करेगी।

इस परियोजना का उद्देश्य उद्यमियों को एक ही वेब पोर्टल पर मानवरहित व पारदर्शी रूप से समयबद्ध सभी प्रकार की अनापत्तियाँ व स्वीकृतियाँ उपलब्ध कराना है। साथ ही वे आवश्यक शुल्कों का भुगतान भी ऑन–लाइन एक ही बार में कर सकेंगे।

राज्य व केन्द्र सरकार के सभी संबंधित विभागों को एकल पोर्टल पर नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस डिलवरी गेटवे के द्वारा इण्टीग्रेट करके सरकार व उद्यमियों के बीच एक सुगम साधन बनाया जाएगा।

परियोजना के प्रथम चरण में राज्य सरकार के विभागों से संबंधित 24 सेवाओं को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा।

———————————————